मनोहर लाल के चंडीगढ़ और करनाल में नवरत्न : पवन बंसल

खुल्लर, ढेसी, अमित अग्रवाल, उमाशंकर, अभिमन्यु और आलोक मित्तल, करनाल में मेयर रेणु बाला गुप्ता, ब्रिज गुप्ता, जगनमोहन आनंद, परदे के पीछे नीरज दफ्तूर, टी सी गुप्ता और अजय गौड़।

चर्चा चंडीगढ़ के नवरत्नों की:-

राजेश खुल्लर : रिटायरमेंट के बाद मनोहर लाल ने अपने पुराने विश्वस्त ढेसी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर खुल्लर को उनकी जगह से नवाजा। अब पोस्टिंग ट्रांसफर और सारे बिगड़े कामों का निपटारा खुल्लर के जिम्मे। खुल्लर की सलाह पर जन समर्थक फैसले और खुल्लर लगे मनोहर की छवि चमकाने।

अमित अग्रवाल: लोक संपर्क महकमे के बॉस अखबारों में विज्ञापन और मीडिया प्रबंधन, आम पत्रकारों से कोई संबंध नहीं और केवल चुनिंदा की जी हजूरी। कभी कभी पिछले चुनाव में 75 पार के नारे के जनक कोई सज्जन भी। **आलोक मित्तल:** काम सूचना देना, लेकिन हस्तिनापुर की निष्ठा से बंधे मुख्यमंत्री को वही बताते हैं जो उनके कान को अच्छा लगता है। **उमाशंकर:** पोर्टल एक्सपर्ट अपने काम से काम राजनीति में नहीं पड़ते। विदुर की तरह सलाह देते हैं। **पीए अभिमन्यु:** सर्वशक्तिमान और मनोहर लाल का खास।

परदे के पीछे:- जवाहर यादव: बिल्डरों और मुख्मंत्री के बीच राम सेतु। **नीरज दफ्तूर:** दिल्ली में सक्रिय। **अजय गौड़:** जमीन एक्सपर्ट और एन सी आर में सक्रिय। **छवि चमकाने के लिए** धर्मदेव पटौदी और स्वयंभू गीता मनीषि स्वामी ज्ञानानंद। **दिल्ली में आका:** मोदी और अमित शाह। **रिमोट कंट्रोल:** कोई अरुण जी, वैसे अरुण जी का प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। बस हर महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए उनके दरबार में सजदा करना पड़ता है।

अपने नवरत्नों और आकाओं के चलते मनोहर लाल जी मस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। असेम्बली चुनाव के पहले मोदी प्रधानमंत्री बना तो मनोहर लाल को उम्मीद कि वे लाट साहब और कांग्रेस में बैठे मोदी के चेलों की मदद से जोड़-तोड़ कर सरकार बना लेंगे। अगर सरकार न भी बनी तो केंद्र में मंत्री या गवर्नर। वैसे यदि बॉस यानी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना तो शायद वियोग में चेला यानी मनोहर लाल असेम्बली चुनाव ही न लड़े। आगे राम जाने...

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

अवैध कॉलोनियों में तो बरसों से है बिजली, खट्टर ने अब कनेक्शन देने की घोषणा की

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) विपक्षी दलों की सरकारों पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाले भाजपाई सीएम खट्टर भी चुनाव करीब आते ही एक के बाद एक मुफ़्त रेवड़ियों की झड़ी लगा रहे हैं। स्वच्छ राजनीति का ढिंढोरा पीटने वाले खट्टर ने पहले तो वोट की राजनीति करते हुए प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी, अब इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा भी कर दी है।

सिद्धांतों की राजनीति का ढोल पीटने वाले खट्टर को यह सलाह देने वाले अधिकारियों ने उन्हें बेवकूफ बनाया या वोट की लालच में खट्टर ने जानते बूझते घोषणा यह की। सर्व विदित है और खट्टर भी यह बात भली भांति जानते हैं कि सभी अवैध कॉलोनियों में बिजली ही नहीं पानी और रोड नेटवर्क बहुत पहले से ही है। बताते चलें कि खट्टर के आदेश पर शहर की 59 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। यदि प्रति कालोनी सौ मकान का औसत माना जाए तो करीब छह हजार मकान हैं, हालांकि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है।

शहर की राहुल कॉलोनी हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई खोरी कॉलोनी, एसी नगर स्लम बस्ती, जमाई कॉलोनी या अन्य सभी अनियमित कॉलोनियां, जब से ये बनी हैं नगर निगम ने इनमें पाइप लाइन और बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं। हर घर में टीवी, फ्रिज, कूलर वाशिंग मशीन जैसे आधुनिक बिजली उपकरण इस्तेमाल होते हैं। खट्टर की घोषणा को माना जाए तो इसका अर्थ है कि इन अनियमित कॉलोनियों में लंबे समय से बिजली भी अवैध रूप से जलाई जा रही थी। यदि खट्टर की घोषणा को माना जाए तो अभी तक इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं था, यानि इन घरों में चोरी से बिजली जलाई जा रही थी।

छह हजार से अधिक घरों में बिजली निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना बिजली नहीं जलाई जा सकती। यानी एक दशक से भी कहीं अधिक समय से बिजली निगम के अधिकारी की देखरेख में बिजली चोरी करवाई जा रही थी। एक अवैध कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लाइन मैन और मीटर रीडर यहां हर महीने आते हैं और घर में उपलब्ध बिजली के उपकरणों के आधार पर सौ रुपये से ढाई सौ रुपये तक वसूलते हैं। जाहिर है कि लाइनमैन या मीटर रीडर यह रकम खुद नहीं हड़प लेता होगा, क्योंकि लाइन लॉस दिखाने वाले तो आला अधिकारी ही होते हैं, उन तक बिजली चोरी की इस कमाई का हिस्सा भी पहुंचता होगा।

सीएम खट्टर की घोषणा का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए स्थानीय विधायक भी अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन का पोस्टर लगा कर वाहवाही लूटने में लगे हैं। यही जन प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बसने में सहयोग किया और इन्हीं लोगों के इशारे पर इन अवैध कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति की गई थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक खट्टर को बिजली चोरी की जानकारी है, उन्होंने चुनाव के पहले यह घोषणा कर अवैध बस्तियों और स्लम के वोटरों को लुभाने की चाल चली है लेकिन इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। वजह यह कि इनमें से अधिकतर लोगों को चोरी की बिजली की आदत पड़ चुकी है। लाइनमैन से लेकर आला अधिकारियों को भी ऊपर की कमाई की आदत पड़ चुकी है। सरकार को दिखाने के लिए कुछ परिवारों को कनेक्शन दे दिया जाएगा जबकि अधिकतर पुरानी व्यवस्था के तहत बिजली जलाते रहेंगे।

बिजली चोरों से होने वाली लूट कमाई की लालच में बिजली निगम के आला अधिकारी तब तक कार्रवाई नहीं करते जब तक रिकॉर्ड मेनटेन करने के लिए ऊपर से दबाव नहीं आए। यही कारण है कि बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय ये अधिकारी हीलाहवाला कर शिकायतकर्ता को ही परेशान करने लगते हैं। यदि किसी बड़े बिजली चोरी करने वाले की शिकायत की जाए तो ये अधिकारी बिजली चोरी के आरोपी को शिकायत और शिकायत करने वाले के नाम की जानकारी देकर मामला सुलटाने की सलाह दे देते हैं। मोटी कमाई के लालची अधिकारी बिजली चोरी रोकने के बजाय शिकायतकर्ता को नगर निगम, पुलिस आदि से शिकायत करने की सलाह देकर हतोत्साहित करने से भी बाज नहीं आते।

प्रदेश के सबसे कमाऊ जिलों में एक फरीदाबाद में लूट कमाई वाला पद ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए अधिकारी केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर, खट्टर के कलेक्शन एजेंट अजय गौड़ जैसे बड़े नेताओं को चढ़ावा चढ़ाते हैं तब कहीं जाकर मलाई वाली कुर्सी हासिल होती है। सीएम खट्टर भी सबकुछ जानते हुए अपने करीबियों की सिफारिश पर मुहर लगा कर 'बड़ी ही ईमानदारी' से शासन चला रहे हैं।

राजनेताओं ने पुराने चोर सतीश पाराशर को....

पेज एक का शेष

किया था। इस इलाके की जमीन का सीएलयू नहीं हो सकता था। ऐसे में सतीश पाराशर ने मोटा सुविधा शुल्क वसूलकर इन पांच फार्म हाउस मालिकों को एलओआई जारी कर दिया था। हालांकि यह मलाई उन्होंने अकेले नहीं खाई होगी लेकिन मामला सामने आने पर अधिकारियों और सरकार ने अपनी फजीहत बचाने के लिए उन्हें निलंबित कर मुख्यालय चंडीगढ़ अटैच कर दिया। विभिन्न पदों पर रहने के दौरान कमाई गई ढेर सारी संपत्ति का कुछ हिस्सा ऊपर खिसका कर उन्होंने गुड़गांव के सीनियर टाउन प्लानर का अधिक कमाई वाला पद हासिल कर लिया।

फरीदाबाद रहते हुए उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर कर कई राजनेताओं के चहेतों के लिए सूरजकुंड-अरावली के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में फार्म हाउस, बैंकट हॉल के लिए जमीन का बंदोबस्त किया था। यही नहीं कई बड़े बिल्डरों से मिलीभगत कर नगर निगम को करोड़ों रुपये राजस्व का चूना भी लगाया। इन्हीं राजनेताओं ने अपने चहेते बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर व भूमाफिया के लिए होनहार सतीश पाराशर को सीटीपी पद पर दोबारा बुलवाया है। फरीदाबाद नगर निगम में करीब एक दशक तक काम करने के कारण उन्हें यहां की परिस्थितयों की पूरी जानकारी है यानी कहां की सीएलयू के कितने रेट हैं, दलाल कौन हैं, किस अधिकारी तक कितना हिस्सा देना होता है।

माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार में डूबे नगर निगम की तरकश में एक और बेहतरीन तीर आ गया है जो अधिकारियों से लेकर नेताओं और भूमाफिया सबको साधने में महारत रखता है।